टीडीसी के दीर्घकालिक हितों की रक्षा जरूरी : नपलच्याल

2007–08 के एजीएम में डेढ़ करोड़ के लाभ की घोषणा

पंतनगर। 10 सितम्बर, 2009। गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गाँधी सभागार में आज उत्तराँचल तराई बीज एवं विकास निगम की वर्ष 2007–08 हेतु 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रदेष के प्रमुख सचिव, वन्य एवं ग्राम्य विकास व उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम (टीडीसी) के अध्यक्ष एन.एस.नपलच्याल ने की।

श्री नपलच्याल ने टीडीसी को इस वर्ष हुये 134.08 लाख रूपये लाभ का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने आलोच्य वर्ष में निगम की 700 करोड़ की परिसम्पत्तियां, लगभग साढ़े चार लाख कुन्तल बीजों के उत्पादन, उत्तराखण्ड सहित देष के अन्य राज्यों में हुए 77.30 करोड़ रूपये के व्यवसाय सहित अन्य विकास योजनाओं की जानकारी दी। निगम के प्रबंध निदेषक व कुलपति डा. बी.एस. बिष्ट ने निगम अध्यक्ष, निदेषक मण्डल सदस्यों व अंषधारी कृषकों का स्वागत करते हुए निगम के कार्यकलापों में अनवरत सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी निगम को विकास के मार्ग पर ले जाने हेतु यहां की पारदर्षी योजनाओं को सफलता का आधार बताया।

इस अवसर पर निगम महाप्रबंधक ए.के.सेठ, कंपनी सचिव आर.के.निगम, कृषक निदेषक जसवंत सिंह पूनिया, त्रिलोक सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। बैठक में उपस्थित अंशधारी किसानों ने निगम के पूर्व निदेशक, श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में अंशधारियों को वर्ष 2008–09 में दिये गये एडवांस रू. 1040.00 प्रति कुन्तल के स्थान पर पूर्व फार्मूले के अनुसार रू. 1095.00 प्रति कुन्तल दिये जाने के लिए अध्यक्ष पर दबाव डाला जिसका सज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने काफी विचार विमर्श के बाद निगम के दीर्घकालिक हितों का ध्यान रखते हुए यह मूल्य रू. 1050.00 प्रति कुन्तल किये जाने की घोषणा की। किन्तु अंशधारियों ने इससे असहमती जताते हुए अपना असंतोष प्रकट किया। इस अवसर पर निदेषक शोध डा. डी.पी.सिंह, मुख्य महाप्रबंधक फार्म डा. ए.के.भारद्वाज, वित्त नियंत्रक अमिता जोषी, एनएससी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेषक कृषि पवन कुमार आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ए.के.लोहनी ने किया।

बैठक के बाद पंत विवि के कुलपति सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री नपलच्याल ने सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, विपणन की कारगर योजना व अंषधारी कृषकों हेतु लाभकारी नीतियों के साथ ही टीडीसी के दीर्घकालिक हितों की रक्षा की वकालत की। पत्रकारों से वार्ता के क्रम में श्री नपलच्याल ने कहा कि प्रदेष विभाजन के बाद टीडीसी के सम्मुख अस्तित्व रक्षा का प्रष्न पैदा हो गया था, मगर यहां के अधिकारियों व अंषधारी कृषकों की दूरदर्षिता के चलते इसे एक बार फिर विकास की राह पर खड़ा होने का अवसर मिला है। भविष्य में भी कृषकों, प्रदेष शासन व निगम अधिकारियों के सहयोग से ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रयास होगा, जिनके सहारे निगम की दीर्घकालिक हितों की रक्षा हो सके। उत्तराखण्ड की अपेक्षा उत्तर प्रदेष स्थित बीज निगम के माध्यम से बीज उत्पादकों को मिल रही अतिरिक्त सुविधाओं के सवाल पर श्री नपलच्याल ने कहा कि यह सत्य है। परन्तु इसके लिए निगम नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की योजना में शामिल शर्तें एक हद तक जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन के तहत उसी प्रदेष को सब्सिडी मिल सकती है, जहां उत्पादन क्षेत्र अधिक होने के बावजूद उत्पादकता काफी कम हो। उत्तराखण्ड में बीज उत्पादन पट्टी का क्षेत्रफल कम होने के बावजूद उत्पादकता काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड को केन्द्रीय अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। इसके बावजूद शासन स्तर पर केन्द्र से पर्वतीय राज्य होने के नाते विषेष सुविधाएं मुहैया कराने की कोषिषें जारी हैं।

ई.मेल.चित्र सं.–2. पंतनगर में आयोजित टीडीसी एजीएम में भागीदारी करते प्रमुख सचिव एन. एस.नपलच्याव (दायें) व एमडी डा. बी.एस. बिष्ट (बायें)